केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 349 शनिवार 13 जुलाई 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत अभी जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली (आभा)। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है लेकिन उनपर केस चलता रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है. लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है. इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा. इसी बीच दिल्ली भाजपा ने बिजली के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला. इस दौरा भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि 'जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बिच का निर्णय है. और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता की आप अपराध मुक्त हो गए हैं।

मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित तीन सवाल उठाए, मामला बड़ी पीठ के पास भेजा. आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया. उन्होंने लिखा, 'मोदी जी, झूठे मामले दर्ज करके सच्चाई को कब तक कैद रखेंगे? पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है. चाहे ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी का मानना है कि केजरीवाल को ईडी ने झूठे मामले में फंसाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है।

स्मृति इरानी के बचाव में आगे आये राहुल गांधी

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणी पर नाखुशी जाहिर की है।

उन्होंने एक्स पर कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। मैं सभी से अपील करता हूं की स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। किसी को बेइज्जत और शर्मसार करना कमजोर होने की निशानी है ताकतवर होने की नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसा न करें।

बता दें कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया था। हालांकि, 2024 के चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीबी किशोरी लाल शर्मा के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। नई सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर लगातार निशाने पर हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर टिप्पणी की है।

25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित

नई दिल्ली (आभा)। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कहा गया, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद उस समय की सरकार की ओर से सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, '25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विशाल योगदान का स्मरण कराएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था।'

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। 'संविधान हत्या दिवस' हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।'

दूसरी ओर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'नॉन–बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों से 4 जून, 2024 (जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा) को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। यह वही नॉन–बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों व संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है।

नेपाल में गिरी पुष्प कमल दहल सरकार

काठमाण्डू (आभा)। नेपाल की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दलह प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है और के पी शर्मा ओली का नया पीएम बनना लगभग तय हो गया है। संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत खो दिया। दरअसल, सीपीएम–यूएमल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 275 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव (एचओआर) में प्रचंड के विश्वास मत के खिलाफ 194 और समर्थन में 63 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए 138 मतों की आवश्यकता थी।

पिछले ही सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन–यूएमएल ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापल ले लिया था। ओली और नेपाली कांग्रेस (नेका) के नेताओं ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के शुक्रवार को होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले नई गठबंधन सरकार के गठन पर मंथन किया था। आपको बता दें के नेकां के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पहले ही ओली को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपना समर्थन दिया है।

नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक के सवालों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को बहुजन मुक्ति पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आये दिन होने वाले पेपर लीक और नीट परीक्षा में धांधली के सवाल को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश गौतम के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर धरना दिया गया। धरने के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निस्तारण की मांग किया गया।

धरने को बहुजन मुक्ति पार्टी के मण्डल अध्यक्ष हृदय गौतम, भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर. के. आरतियन ने सम्बोधित किया। कहा कि पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। इसे तत्काल रोका जाय।

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में नीट परीक्षा की धांधली में जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्यवाही किये जाने, परीक्षा निजीकरण के स्थान पर सरकारी प्रशासन के नियंत्रण करायी जाय, दुबारा परीक्षा निःशुल्क और निष्पक्ष कराई जाए तथा किसी भी परीक्षार्थी से इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी फीस न ली जाने, धांधली करने वाले निजी संस्थाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाये जाने, धांधली में जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कड़ी कार्रवाई किये जाने आदि की मांग शामिल है। धरना और ज्ञापन सौंपने वालों में लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर प्रेमनन्दबंशी, रितिक कुमार, बुद्धेश राना, विमला देवी, डा. रिफाकत अली, मो. जावेद, सुनील कन्नौजिया, कुंवर भीम सिंह, रामलेस के साथ ही अनेक लोग शामिल रहे।

निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करें अधिकारी–डीएम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने–अपने विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय–सीमा में अवश्य पूर्ण करें। उन्होने कहा कि संबंधित अधिकारी शासन के विकास प्राथमिकताओं/कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि ना बरती जाय। उन्होने कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्यो की स्वयं समीक्षा करें एवं प्रगति में सुधार लायें।

जिलाधिकारी ने शासन की विकास प्राथमिकताओं/कार्यक्रमों की विभागवार/योजनावार समीक्षा के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट, प्रधानमत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम, सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, 15वां वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, आपरेशन कायाकल्प, अण्डा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, शादी अनुदान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, प्रोजेक्ट अलंकार, नयी सड़कों का निर्माण, कन्या विवाह सहायता, ओडीओपी टूलकिट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, टेल फीडिंग योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

बैठक में दुग्ध विकास के संबंधित अधिकारी अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होने विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश संबंधित को दिया है।

उन्होने कर–करेत्तर से संबंधित विभागों के अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक भी किया। उन्होने आबकारी, स्टम्प व रजिस्ट्रेशन, वाणिज्यकर, परिवहन, खनन, बाट माप, श्रम, नगरपालिका, विद्युत, चकबन्दी, भू–राजस्व, सामाजिक वानिकी, मण्डी सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें। बैठक में विद्युत, वाणिज्यकर विभाग द्वारा वसूली कम पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल चौहान, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, पीडी राजेश झा, एसडीएम आशुतोष तिवारी, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र वर्मा, आबकारी अधिकारी, एआरटीओ पंकज कुमार, बीएसए अनूप तिवारी, डीपीआरओ रतन कुमार, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. राजेश त्रिपाठी, पीओ डूडा सुनीता सिंह, एआरएम आयुष भट्टनागर, संबंधित तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भाजपा ने शुरू किया मतदाता अभिनन्दन समारोह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लोकसभा चुनाव परिणाम एवं तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा ने विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। भाजपा नेता अमृत कुमार वर्मा ने बताया की बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता नही मिली इसके बावजूद भी भाजपा अपने वोटरों को सहेजने में कोई कसर नही छोड़ना चाहती। बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल लगभग 4 लाख 26 हजार वोट मिले। इन वोटरों का सम्मान करने के लिए भाजपा विधानसभा वार मतदाता अभिनन्दन समारोह का आयोजन कर रही है। दो दिवस में प्रस्तावित यह कार्यक्रम 12 जुलाई को विधानसभा रुधौली के सल्टौआ ब्लाक समागार में, कप्तानगंज में बभनान बाजार, हरैया में ब्लाक समागार में संपन्न हुआ, 13 जुलाई को बस्ती सदर में अटल बिहारी श्रेक्षागृह बस्ती और महादेवा विधानसभा के शिक्षा शक्ति मैरेज हाल कुदरहा में होना है। भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का लोकसभा चुनाव में दिए गए योगदान को लेकर आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ व प्रबुद्ध मतदाताओं को निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने भगवा अंगवस्त्र पहना कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्रमवार हजारो मतदाता सम्मानित हुए।

निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां मतदाता ही सर्वोपरि है। मतदान से ही सरकारें बनती है। मतदाता ही तय करते हैं कि किस दल की सरकार देश और प्रदेश की उन्नति और विकास की गति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुये कहा सपा और कांग्रेस ने संविधान के नाम पर लोगो को गुमराह करने का काम किया। आपातकाल के हालातो को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया वह पूजनीय है। मितरघातियो से भी संगठन जल्द ही निपटेगी। उन्होने केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर मतदाताओं का अभिवादन किया।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ है। उनके ही मेहनत ने पूरे देश में रंग लाई है। आने वाले विधानसभा में हम भारी बहुमत से फिर सरकार बनायेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर मतदाता ही देश में सरकार चुनते हैं। मतदाताओं ने देश में ऐतिहासिक रूप से नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उसके सही क्रियान्वयन पर जनता की मुहर लगी है। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर यशकांत सिंह, राना नागेश सिंह, प्रत्युष विक्रम सिंह, दुर्धांत सिंह, कुँवर आनन्द सिंह, देवेन्द्र सिंह, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, राम श्रिंगार ओझा, सुरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, वरुण सिंह, वीरेन्द्र गौतम, राम निवास गिरी, राजकुमार चौरसिया, श्यामनाथ चौधरी, सुजीत सोनी, अतुल यादव, राकेश शर्मा, चंद्रभान गुप्ता, ओम प्रकाश शुक्ल, बलराम सिंह, विनय शंकर मिश्र, राम चरन चौधरी, रवि सिंह, मनोज ठाकुर, मगन शुक्ल, प्रबल मालानी, आनन्द सिंह कलहंस, वीरेन्द्र मिश्र, विनोद चौधरी, भोला निषाद, विजय गुप्ता, वरुण पाण्डेय, राधेश्याम कमलापुरी, जटाशंकर शुक्ल, अरविन्द सिंह, राजेंद्र राजभर, मनोज पाठक, सुनील त्रिपाठी, श्रीश पाण्डेय, समीर चौहान, शिव चरन जायसवाल, मनीष सिंह, जवाहर लाल जायसवाल सहित मतदाता मौजूद रहे।

—लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि– हरीश द्विवेदी

जूनियर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, ऑन लाइन हाजिरी का फैसला वापस ले सरकार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल 'पूर्व माध्यमिक' शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय के नेतृत्व में जिला अधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन के निर्णय को वापस लिये जाने के साथ ही शिक्षक समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद अम्बिका पाण्डेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय की पंजीकाओं का डिजिटलाइजेशन व डिजिटल (डिजिटल फेस छायांकन) उपस्थिति कराए जाने संबंधी निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। कहा कि पिछले 4 दिनों से समूचे प्रदेश के लगभग 6 लाख शिक्षक डिजिटलाइजेशन का मुखर विरोध कर रहे हैं इसके बावजूद सरकार और परिषदीय अधिकारियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। कहा कि सरकार मांगों को तत्काल पूरा करने की दिशा में पहल करे।

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाओं को हॉफ सी०एल० की सुविधा दिये जाने, 30 ई०ए०एल की सुविधा देने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा (बिना प्रीमियम) दिये जाने, ससमय स्थानानतंरण, पदोन्नति दिये जाने, वेतन विसंगति समस्या का निराकरण करने, लिपिक की नियुक्ति करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किये जाने, शिक्षक, शिक्षिकाओं के जनपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किये जाने आदि की मांग शामिल है।

ज्ञापन सौंपने वालों में मंत्री मोहम्मद इजहारूल हक, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, उमेश मौर्य, मोहम्मद आलम, फूलचंद, डा. राजेश सक्सेना, बृजेश कुमार, विश्राम राव आशुतोष कुमार पाण्डेय, जया कुमारी, मनीष कुमार मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद, संतोष कुमार, अशोक राव, कृपा शंकर, बाबू लाल, आदि संगठन के पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे।

कुछ सभासदों ने किया नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार, लगाये गंभीर आरोप

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। कुछ सभासदों ने सभासद रमेश कुमार गुप्ता, गौतम यादव, राजन ठाकुर, पंकज चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी के नेतृत्व में नगर पालिका में मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुये बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। नाराज सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा की जगह उनके जेठ विवेक वर्मा काम काज देखते हैं और 25 वार्डों में योजनाओं का मनमाना तरीके से वितरण कराया जाता है। कुछ वार्डों में सर्वाधिक धन के प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तो कई वार्ड अछूते रह गये हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आखिर सभासद अपने वार्डों में जनता को क्या मुंह दिखायें। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तक की तैनाती नहीं कराया गया।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करने वाले रमेश कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार चौधरी आदि ने कहा कि बरसात के दिनों में अनेक वार्डो में नालियों की साफ–सफाई नहीं हो पा रही है। वार्डो में जल जमाव है। नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डों के टोटियों में जल पिछले एक वर्ष नहीं आ रहा है। अनेकों बार शिकायत की गई किन्तु समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पटल सहायकों द्वारा कार्यों को ठीक ढंग से नहीं किया जाता। मांग किया कि सभी 25 वार्डो में विकास कार्यो के समान वितरण के साथ ही पुनः बोर्ड की बैठक बुलाकर समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय।

बोर्ड के बैठक का बहिष्कार करने वालों में रमेश कुमार गुप्ता, राजन ठाकुर, पंकज चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी, गौतम यादव, रविन्द्र कुमार, ममता सोनकर, रोली चौधरी, अमरावती देवी, निर्मला देवी, रूकैया खातून, इन्द्रावती देवी, विद्यावती सोनकर, बैजयन्ती सिंह, लारा चौधरी, अरविन्द सोनकर, शोभी सोनकर, प्रमोद गुप्ता, अभीजीत सिंह, उमेश प्रजापति के साथ ही सभासद और उनके प्रतिनिधि शामिल रहे।

कुछ सभासदों का आक्रोश स्वाभाविक, मिल बैठकर होगा समस्याओं का समाधान– नेहा वर्मा

—अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति के लिये जारी है प्रयास

बस्ती। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने शुक्रवार को आयोजित बोर्ड की बैठक का कुछ सभासदों द्वारा बहिष्कार किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि सभासदों की मांग जायज है और वे लगातार प्रयास कर रही है कि नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी कार्यभार संभाले। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर पत्राचार के साथ ही व्यक्तिगत रूप से नगर विकास मंत्री से मिलकर आग्रह किया गया है कि अति शीघ्र अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाय।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि कार्य भार संभालने के बाद से ही उनका प्रयास रहा है कि नागरिकों से जो वायदे किये गये हैं उस अनुरूप कार्य धरातल पर कराया जाय। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती आगमन पर उन्हे सीवर लाइन, सड़कों के निर्माण और गांधीनगर में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया है जिस पर मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र पहल का आश्वासन दिया गया है। अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि सभी 25 वार्डों के समुचित विकास, नाली, खण्डजा निर्माण, साफ–सफाई प्रकाश व्यवस्था आदि का कार्य कराया जाता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यभार न संभाले जाने को लेकर सभासदों का गुस्सा स्वाभाविक है। कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि असहमतियों को दूर करने के साथ ही प्रभावी ढंग से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जिससे विकास कार्यो को गति दी जा सके। सभी वार्डो का समुचित और संतुलित विकास उनकी प्राथमिकता है। कहा कि सभासदों की नाराजगी को मिल बैठकर दूर कर लिया जायेगा। अति शीघ्र पुनः बोर्ड की बैठक बुलाई जायेगी।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 13 जुलाई 2024 शनिवार

सम्पादकीय

भरण पोषण का अधिकार

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण–पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण–पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण–पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण–पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकार को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण–पोषण के अधिकारों का उत्तरोतर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब हम 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता के चलते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेदन के बाद भी महिला को भरण–पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। निस्संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले का मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाकशुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण–पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन–यापन का संकट बड़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाकशुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाकशुदा बेटियों का जीवन–यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागतयोग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था। जिसके बाद देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला था। निस्संदेह, चार दशक बाद अब भारतीय समाज में लैंगिक समानता को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया है।

बजट पर टिकी मध्यम वर्ग की निगाहें

–डा. जयंतीलाल भंडारी–

इन दिनों पूरे देश के साथ–साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024–25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आयी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश की जा सकती है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र था कि मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाएगा।

गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024–25 के समय आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023–24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और बीते 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013–14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019–20 में 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह 2020–21 में कुछ घटा। लेकिन 2021–22 में 14.08 करोड़ रुपये, 2022–23 में 16.64 करोड़ रुपये और वर्ष 2023–24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।

ऐसी मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहतों से लाभान्वित किया जा सकता है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह धनराशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिए घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं जहां आमदनी कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। वेतनभोगी वर्ग द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाता वर्ग द्वारा चुकाए गए आयकर से काफी अधिक होता है।

नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्पेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। इसके साथ–साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।

निःसंदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024–25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान संभव है। महत्वपूर्ण यह भी कि बड़ी संख्या में उद्योग–कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा महंगी कारें खरीदी, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे वहीं वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर विदेश यात्राएं कीं। जाहिर है पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियां और विदेश यात्राएं संभव हैं। लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। बता दें कि वर्ष 2023–24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शून्य आयकर देयता बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। वहीं अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी–छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संगृहीत किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है।उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

—लेखक अर्थशास्त्री हैं।

बढ़ते सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन...?

—रोहित माहेश्वरी—

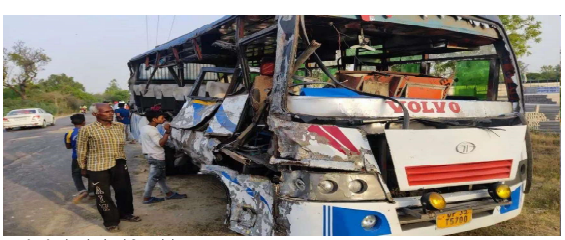

बीते 10 जुलाई को बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेसवे पर यूपी के उन्नाव जिले में दुर्घटना की शिकार हो गयी और इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गयी। हादसे के बाद बस के सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगा है। लोग भी हादसा होने के बाद सीख नहीं ले रहे हैं। असल में देश में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए वाहन चालक, सरकार और प्रशासन संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। सड़क हादसों के कई कारण हैं। शराब पी कर वाहन को तेज चलाने और स्टंट करने से भी सड़क हादसे हो रहे हैं। इसलिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव बस हादसे का शिकार हुई बस का ड्राइवर नशे में था– यह बात सामने आ चुकी है।

30 मई को जम्मू–कश्मीर में अखनूर के पास एक बस के गहरी खाई में गिरने से 20 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत फिर से यह बता रही है कि अपने देश में किस तरह आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोग बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाते हैं। इस बस दुर्घटना का कारण यह माना जा रहा है कि ड्राइवर या तो तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसके चलते वह सामने से आती कार को बचाने में अपना नियंत्रण खो बैठा या फिर उसे झपकी आ गई होगी।

दुर्घटना का मूल कारण कुछ भी हो, जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। यह ठीक है कि राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया और इस हादसे पर राष्ट्रपति समेत प्रमुख नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं, लेकिन यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के ठोस उपाय कब किए जाएंगे? बार–बार यह तथ्य सामने आ रहा है कि भारत में कहीं अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवाने के साथ जख्मी भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिनसे सड़क हादसों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगे।

तेज गति और नशा करके वाहन चलाने, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करने, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने और सड़कों पर गड्ढों के कारण सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं।यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह भ्रष्टाचार भी है नागरिकों में भी जागरूकता की कमी है। खासकर युवा असंयमित रूप से वाहन चलाते हैं। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार होने और लापरवाही के कारण सड़क जल्दी टूट जाती है। सड़क पर बने गड्ढे हादसे की वजह बनते हैं।

देखने मे ये आ रहा है कि यातायात पुलिस लाइसेंस को लेकर सख्त नही है। बिना लाइसेंस के गाडी चलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए ताकि अपात्र लोग लाइसेंस न बन पाएं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए ताकि सभी नियमों और संकेतकों की जानकारी वाहन चालक को हो।

भारत में कई ड्राइवर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार अभियानों चलाने की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कठोर सजा भी आवश्यक है।

भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में एक साल में मारे जाते हैं, इसलिए चिंतित सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते जितने सडकों पर गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। पिछले एक दशक में ही भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। चूंकि सड़क हादसे रोकने के आवश्यक उपाय नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए उनमें मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में एक लाख 68 हजार लोगों की जान गई। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में कहीं कम संख्या में वाहन हैं। इन मौतों का दुष्प्रभाव तो मृतकों के परिवार पर पड़ना स्वाभाविक ही है साथ ही देश की प्रगति भी इन हादसों से प्रभावित होती है।

मार्ग दुर्घटनाओं के कारण किसी से छिपे नहीं। यातायात नियमों का उल्लंघन, खटारा वाहन, अकुशल चालक सड़क हादसों के मूल कारण हैं। ये ऐसे कारण नहीं, जिनका निवारण न किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि देश के किसी न किसी हिस्से में करीब–करीब प्रतिदिन कोई न कोई बड़ा सड़क हादसा होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं अथवा गंभीर रूप से घायल होते हैं। सड़क संरचना और इसके रखरखाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं में गति के प्रति आकर्षण से भी सड़क हादसों में वृद्धि हुई है। स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में यातायात नियमों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

शासन–प्रशासन इन हादसों पर शोक संवेदना जताकर कर्तव्य की इतिश्री तो कर लेता है, लेकिन यह देखने से इनकार करता है कि उन्हें रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले अधिकांश लोग अपने घर के कमाऊ सदस्य होते हैं। उनके न रहने से परिवार विशेष को ही क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि समाज और राष्ट्र भी किसी न किसी रूप में कमजोर होता है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद अभी जितना है, उसमें हर साल तीन प्रतिशत की और बढ़ोतरी होती, यदि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में इतने अधिक लोगों की जान न जाती।

सड़क दुर्घटनाओं के लिए सरकार और खराब सड़कों को दोष देना तो आसान है, मगर लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाते समय हेल्मेट और सीट–बेल्ट न पहनना आदि हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ''ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2018'' के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 4 प्रतिशत शराब पीकर वाहन चलाने वालों की होती है। इसी प्रकार दुर्घटना में मरने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 86 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 14 प्रतिशत है। जाहिर है कि महिलाएं अधिक सावधानी से वाहन चलाती हैं।

यातायात पुलिस को जागरूकता अभियान के माध्यम से जनकृजन तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाना चाहिए। अभिभावकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को यातातात नियमों के बारे में जरूर जागरूक करें। नियंत्रित गति सीमा, यातायात नियमों का पालन और शांत दिमाग से वाहन चाल करके हम इस प्रकार के सड़क हादसों से बच सकते है। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जाए। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो सबसे पहले जो वाहन चालक निर्धारित गति से तेज चलाए उसका लाइसेंस निरस्त कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। यातायात पुलिस को भी पूरी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।

पीडीए बनाम डीपीए की राजनीति

— कमलेश पाण्डेय—

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिछड़ा– दलित–अल्पसंख्यक समीकरण यानी 'पीडीए' की अप्रत्याशित सफलता के बाद उसकी असरदार काट भी भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली है और जवाबी दलित–पिछड़ा–अगड़ा समीकरण यानी 'डीपीए' का स्वर बुलंद कर दिया है। समझा जा रहा है कि देश को सर्वाधिक पीएम देने वाले यूपी से शुरु हुई पीडीए बनाम डीपीए की गोलबंदी देर–सबेर हिंदी भाषी सभी राज्यों से होते हुए गैर हिंदी भाषी राज्यों तक पहुंच जाएगी और सियासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ेगी।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि एक तरफ सामाजिक न्याय आंदोलन (मंडल आंदोलन) से निकली समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए मुहिम के सहारे जहां अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सहेजते हुए हासिल कर ली है, वहीं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व (कमंडल आंदोलन) से मजबूत हुई भाजपा अपनी उदार राजनीति की वजह से हालिया झटका खाने के बाद फिर से संभलने के लिए अपने पुराने वोट बैंक को सहेजने के प्रयास डीपीए के मार्फत तेज कर चुकी है।

चर्चा है कि अब तक अगड़ों व दलितों की श्लीमित उपेक्षाश करके ओबीसी को बढ़ावा देने वाली और पसमांदा अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए अथक परिश्रम करने वाली भाजपा को जब आम चुनाव 2024 में यूपी समेत कई राज्यों में रणनीतिक झटका लगा तो उसका ओबीसी वाला शुरुर काफूर हो गया और अब तक का सारा सियासी गुरुर चकनाचूर हो गया। क्योंकि उत्तरप्रदेश जैसे अहम राज्य में ही उसकी स्थिति चिंताजनक समझी जाने लगी, जबकि यहां पर उसकी एक मजबूत सरकार भी है, जिसका नेतृत्व फायर ब्रांड हिन्दू नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।

बावजूद इसके, कड़वा सच है कि उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से सपा प्रमुख व ओबीसी नेता अखिलेश यादव के अप्रत्याशित उभार से यानी एकाएक बनी तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया समझे जाने से ओबीसी पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सवर्ण–दलित विरोधी टीम के होश फाख्ता हो चुके हैं। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह ने यह समझ लिया है कि अब तक जिस ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए वे लोग अथक परिश्रम करते आ रहे हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष आदि में ऑख मूंद कर बढ़ावा दे रहे हैं, वह मूलतः समाजवादियों का वोट बैंक रहा है, जो यूपी आदि राज्यों में एक बार फिर समाजवादी मूल के क्षेत्रीय दलों की ओर शिफ्ट हो गया।

जबकि दलित कांग्रेस व दलितवादी दलों के मूल वोट बैंक हैं, जो दलितवादी दलों की अनुपस्थिति में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दिए। उधर, आदिवासी वोट भी भाजपा और कांग्रेस में बंट रहे हैं। वहीं, भाजपा समर्थक अगड़ों में भी नीतिगत उपेक्षा के चलते रोष दिखा और उनका एक मजबूत धड़ा भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों से जुड़ गए या फिर मतदान में उदासीन बना रहा, जिससे वोटिंग का ग्राफ गिरा।

वहीं, अल्पसंख्यक वोट जहां पहले स्थानीय रणनीति के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादियों में बंटते आए हैं, लेकिन अब यह अल्पसंख्यक वोट भी संसदीय चुनाव में कांग्रेस व उसके मित्र दलों की ओर और विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है, वहां कांग्रेस मूल के क्षेत्रीय दलों या समाजवादी आंदोलन मूल की स्थानीय पार्टियों की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। तीन तलाक प्रथा बंद करने हेतु कानून बनाने के बाद मुस्लिम महिलाओं का जो रुझान भाजपा की ओर बताया गया, वह भी आम चुनाव 2024 में नहीं दिखा। उधर पसमांदा मुसलमानों ने भी भाजपा पर भरोसा नहीं किया।

महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया जेठ

संवाददाता–गोण्डा। खेत जाते समय जेठ ने महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है।

छपिया थाना क्षेत्र के सिसई रानीपुर गांव में बजरंगी प्रजापति की पत्नी आशा (45) शुक्रवार की सुबह घर से खेत के लिए जा रही थी। वह घर से 100 मीटर दूर सड़क पर पहुंची थी तभी पीछे से पहुंचे उसके जेठ राम अवतार उर्फ खुड्डबुड्ड ने धारदार हथियार से गले पर वारकर दिया। जिससे गंभीर रूप से घायल आशा ने दम तोड़ दिया। आसपास के ग्रामीणों के शोर मचाने पर घटना को अंजाम देते ही जेठ वहां से फरार हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना छपिया पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी मनकापुर आरके सिंह व थानाध्यक्ष छपिया कृष्ण गोपाल राय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। वहीं, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना का निरीक्षण कर शीघ्र खुलासे व आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया।

इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

आशा की हत्या करने वाले आरोपी ने वर्ष 1992 में भी गांव की ही बसंती पत्नी बंशी गुप्ता की हत्या कर दी थी। वह चार साल पहले वर्ष 2020 में जेल से छूटकर बाहर आया था। वह इन दिनों गांव में ही रह रहा था। हत्यारोपी राम अवतार उर्फ खुड्डबुड्ड की शादी नहीं हुई थी। वर्तमान में उसकी उम्र करीब 65 साल है। अब एक बार फिर महिला की हत्या उसने क्यों की, इसको लेकर गांव में तरह–तरह की चर्चाएं हैं फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

महिला समेत दो की संदिग्ध हालात में मिली लाश

संवाददाता–श्रावस्ती। महिला समेत दो लोगों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक के भाई ने मौत पर आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।

नवीन मांडर्ण थाना श्रावस्ती क्षेत्र के ग्राम पंचायत श्याम देवरिया के मजरा महदेईया निवासी हंसीना (40) पत्नी मोहर्रम अली उर्फ मूसे का शव संदिग्ध अवस्था में गन्ने के खेत से बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि हसीना सुबह शौंच के लिए बाहर गई थी। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी खोज करने लगे। तलाश के दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रकरण की जांच करायी जा रही है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी तरह हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरनिया के मजरा टड्वा गांव निवासी हसीबुद्दीन (32) पुत्र अकबाल गुरुवार दोपहर में घर से निकला था और रात में घर वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार सुबह श्रावस्ती जनपद से सटे हुए बहराइच जनपद परिक्षेत्र में हसीबुद्दीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रिसिया मिर्जापुर मार्ग के कटलिया चौराहे के पास बरामद हुआ। सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव देखते ही उनमें चीख पुकार मच गई। सूचना पुलिस को दी गई। चूंकि शव मिलने का स्थाल बहराइच जनपद के रिसिया थाना क्षेत्र में आता है। इसलिए रिसिया पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर अपने भाई की मौत पर आशंका जताई है और जांच की मांग की है।

बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत, दो अन्य गंभीर घायल

संवाददाता–गोण्डा। गोंडा–अयोध्या राजमार्ग पर चंदापुर के पास बृहस्पतिवार की रात बरात जाते समय बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को सीएचसी वजीरगंज ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगवा गड़रियन पुरवा निवासी फूलचंद पत्नी रेनी देवी के भतीजे अकबरपुर–मिश्रौली निवासी सूरज के साथ बृहस्पतिवार की रात बाइक से परसापुर गांव से पत्नी के मामा के बेटे की शादी में वजीरगंज बरात जा रहे थे। दोनों की बाइक गोंडा–अयोध्या हाइवे पर चंदापुर गांव के पास सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। भिड़ंत में फूलचंद (25) व सूरज (19) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी बाइक पर सवार वजीरगंज थाना क्षेत्र के चंदापुर हजारी पुरवा निवासी भगवानदास भारती (55) और इसी गांव के उनके साथी राजकुमार भारती (18) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे की सूचना

पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। थानाध्यक्ष वजीरगंज अभय सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

रिश्तेदार दो युवकों की सड़क हादसे में मौत की खबर उनके घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। फूलचंद के बड़े भाई लालचंद ने बताया कि फूलचंद तीन भाइयों में दूसरे नंबर थे। माता–पिता की अरसा पहले मौत हो चुकी है। फूलचंद की दो साल पहले शादी हुई थी। उसके नौ माह की एक बेटी है। फूलचंद मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता था। पत्नी अपने नानिहाल परसापुर में थी। हादसे में पति की मौत की सूचना मिलने पर शुक्रवार की सुबह सुसराल पहुंची। पति की मौत से उसका रो–रोकर हाल–बेहाल है। सूरज तीन भाइयों में दूसरे नंबर था। उसके तीन साल की एक बेटी है। सूरज की पत्नी भी पति की मौत से बेसुध हो गई है।

सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, एक गंभीर

संवाददाता–श्रावस्ती। दो अलग अलग हादसों में बाइक सवार तीन युवक गंभीररूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिरसिया थाना क्षेत्र के जोगा गांव निवासी शाहिद (23) पुत्र चांदे व अली हुसैन (35) पुत्र मोलहे शुक्रवार सुबह बाइक से भिनगा ताजिया लेने आ रहे थे। भिनगा जंगल में वन निगम डिपो के पास पहुंचते ही बोलेरो से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीररूप से घायल हो गए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने अली हुसैन को मृत घोषित कर दिया। वहीं हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद शाहिद को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। दूसरी सड़क दुर्घटना इकौना थाना क्षेत्र में हुई। इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम कंजड़वा निवासी आत्माराम यादव (25) पुत्र रक्षाराम यादव गुरुवार को पत्नी के साथ बाइक से गिलौला थाना क्षेत्र माजरे गांव अपनी ससुराल में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गया था। पत्नी को ससुराल में ही छोड़कर वह रात करीब एक बजे कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहा था। इस दौरान नेशनल हाइवे 730 पर स्थित गोविन्दपुर सेमगडा मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। आत्माराम काफी देर तक घटनास्थल पर लहुलुहान अवस्था में पड़ा रहा। हादसे की सूचना पाकर डायल 112 पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर इकौना थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह टीम के साथ सीएचसी पहुंचे और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले नहीं हो पा रही थी मृतक की पहचान–मृतक आत्माराम की पहचान नहीं हो पा रही थी।

रुपईडीहा भारतीय इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के तीन अधिकारी बर्खास्त

संवाददाता–बहराइच। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रुपईडीहा स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोर्सट के तीन उच्चाधिकारियों को पद से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई आईसीपी की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के चेयरमैन ने नेपाल की महिला के सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के आधार पर की है। बिना जांच उच्चाधिकारियों को पद से हटाने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

भारत–नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सामरिक, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने व पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार की पहल पर रुपईडीहा बार्डर पर आईसीपी यानि इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का संचालन शुरू किया गया है। भारतीय क्षेत्र के आईसीपी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से दिल्ली की संडलियम कंपनी को सौंपा गया है। आईसीपी के संचालन को अभी चार माह हुए हैं, इस बीच कर्मचारियों की तैनाती को लेकर कंपनी विवादों के घेरे में है। पहले कर्मियों की ओर से शोषण के आरोप लगाए गए अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बिना जांच किए कंपनी के चेयरमैन की ओर से प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी व तकनीकी अधिकारी को पद से ही हटा दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नेपाली महिला आईसीपी से होकर जा रही मैत्री बस से वतन वापस जा रही थी। आईसीपी पर जांच के दौरान किसी कर्मी ने उसका वीडियो बना लिया।

महिला के विरोध करने पर प्रबंधक की ओर से जांच कराई गई। जिसके बाद वीडियो को डिलीट कराकर मामला शांत हो गया। किसी ने महिला का वीडियो गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रबंधक बीएस सिसोदिया, सुरक्षा अधिकारी वंशराज, टेक्निकल इंजीनियर नवजोत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। हटाए गए तीनों अधिकारियों का आरोप है कि बिना उनका पक्ष जाने व वायरल वीडियो की जांच के ही कार्रवाई की गई है। हालांकि 15 जुलाई को चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखेंगे। वैसे कंपनी ने तत्काल प्रभाव से प्रबंधक पद पर वेद प्रकाश ज्येल की तैनाती कर दी है, ताकि आईसीपी के संचालन में कोई दिक्कत न हो। हालांकि यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।

नेपाली महिला ने बताया कि जिस वीडियो के आधार पर आईसीपी के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उस महिला का पक्ष आया है। नेपाली महिला ने वीडियो को गलत तरीके से प्रसारित करने का आरोप लगाया है। ऐसे में तीन अधिकारियों को पद से हटाने की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं।

एमडी ने कहा कि आईसीपी के संचालन को सिर्फ अभी चार माह हुए हैं। इस दौरान 14 कर्मचारियों को बिना किसी वजह के निकाला गया है। नामित कंपनी की ओर से उठाए गए कदम से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। विजय कुमार त्रिपाठी, सुखवीर सिंह, शुभम त्रिपाठी, प्रभाकर, आशीष त्रिपाठी, अदित्य सिंह, विनय मिश्र, सिमरन गुप्ता, भीमराज मौर्य, नरेंद्र कुमार यादव, रविन्द्र प्रताप सिंह, दीपमाला वर्मा व अर्जुन वर्मा का आरोप है कि दो माह का वेतन दिए बिना ही उनको हटा दिया गया है। अब वे लोग हक की लड़ाई के लिए आईसीपी पर प्रदर्शन करेंगे। आईसीपी का बेहतर तरीके से संचालन को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लापरवाह लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है।

टेमरनाला में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत

संवाददाता–महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रजौड़ा खुर्द निवासी 10 वर्षीय मासूम की टेमरनाले में डूबने से मौत हो गई। बृहस्पतिवार देर शाम बालक नाले में डूब गया था। शुक्रवार सुबह नाले में शव उतराया मिला।

जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को महिलाएं पूजा पाठ के लिए टेमर नाले के लुलीघाट पर गई थीं। उनके साथ रजौड़ा खुर्द निवासी रामदवन मौर्य का 10 वर्षीय पुत्र राज मौर्य भी गया था। इस दौरान राज पानी में खेलने लगा। लोगों ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और पानी में फिर से चला गया। अचानक गहराई में जाने से डूब गया।

यह देख महिलाएं चिल्लाने लगीं तो शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण बालक को पानी में तलाश करने लगे, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका। तभी तेज बारिश होने लगी। सब लोग थक हारकर खोजना बंद कर दिए। घटना की सूचना पुलिस को दी। शुक्रवार की सुबह पांच बजे उसी स्थान पर बालक का उतराता हुआ शव मिला। राज अपने माता–पिता का एकलौता पुत्र था। एक छोटी बहन अंशिका छह वर्ष है। मां गुंजा का रो रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष पनियरा निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

द्वारकाधीश भगवान का 15 वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। वैष्णो नगरी अयोध्या में परिक्रमा मार्ग राजघाट स्थित द्वारकाधीश भगवान 15 वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ तीन दिनों तक मनाया गया। वार्षिकोत्सव समारोह का समापन शुक्रवार को भगवान श्री द्वारकाधीश का महा अभिषेक श्रृंगार आरती व भंडारे के साथ हुआ। द्वारकाधीश भगवान का वार्षिकोत्सव 10 जुलाई से जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी सूर्यनारायणाचार्य जी महाराज के सानिध्य में वैदिक विद्वानों द्वारा भूमि पूजन और द्वारकाधीश भगवान के पूजन पाठ से प्रारंभ हुआ जो निरंतर तीन दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी ने बताया कि आज से 15 वर्ष पहले भगवान द्वारकाधीश अपने गर्भगृह में विराजमान हुए थे और प्रतिवर्ष उनका वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जिसमें भगवान का विशेष श्रृंगार महा आरती महा अभिषेक और विधिवत पूजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि बड़े ही सौभाग्य की बात है की प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में द्वारकाधीश भगवान का भी दर्शन और आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। भगवान के वार्षिकोत्सव में अयोध्या के साथ–साथ देश के अन्य विद्वत संतो को बुलाया जाता है। संतो के सानिध्य में भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है और शाम के सत्र में संतों का आशीर्वचन एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा जिसमें अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कोने–कोने से आए संत विद्वान आश्रम के भक्त सम्मिलित होंगे। स्वामी जी ने बताया श्री द्वारकाधीश भगवान के महाअभिषेक बैकुंठ धाम मंदिर के महंत जगतगुरु स्वामी श्यामनारायणाचार्य संत गोपाल मंडपम के पीठाधिपति जगतगुरु स्वामी कूरेशाचार्य महाराज,गोविंद शास्त्री सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लान्ड्रिंग का केस

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने पूर्व विधायक पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिले के टॉप टेन माफिया की सूची में इनका नाम है। प्रशासन ने अब तक इनकी करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया है।

आरिफ अनवर हाशमी बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर थाने के अहिरौली गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 2007 से 2012 तक सादुल्लाहनगर विधानसभा सीट से सपा के विधायक रहे। इनके खिलाफ बलरामपुर जिले के विभिन्न थाने में 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें अधिकांश मुकदमे जमीन हड़पने के है। थाने की जमीन कब्जा किए जाने के मामले में बीते वर्ष तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने जांच कराई जांच के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। साल 2023 में लखनऊ, उत्तरौला और सादुल्लाहनगर को मिलाकर इनकी करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी वर्ष बलरामपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने इनकी संपत्ति जांच करने की संस्कृति की थी। बैंक खातों में जमा धनराशि जमीन, मकान वाहन सहित अन्य प्रॉपर्टी के खरीदे बेचे जाने को लेकर लिखा पढ़ी की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिससे परिवार और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है।

बलरामपुर पुलिस के अधिकारी सिर्फ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहां से रिपोर्ट भेजी गई है।

चौकीदार पर वसूली का आरोप, एसपी से शिकायत

संवाददाता–बहराइच। अभी तक पुलिस महकमे में प्राइवेट वाहन चालकों से धन वसूलने के किस्से सुनने में आते रहे हैं। अब गांव का एक लाल गमछाधारी चौकीदार भी नकदी व गोश्त भेजने का फरमान भेज रहा है। मांग पूरी न होने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दी। जिसके बेअसर होने पर जबरन पीड़ित के दो बकरे खुलवा लिए। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस इसे रफा–दफा करने की जुगत भिड़ा रही है। हुजूरपुर थाने के भूपानी ग्राम निवासिनी मोमिना पत्नी मुस्तफा उर्फ अंगनू ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि गांव के चौकीदार ने पहले फोन पर उनके पति से एक हजार रुपए व गोश्त की मांग की। मांग पूरी न करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। जब यह धमकी भी बेअसर रही, तब चौकीदार ने उसके सहयोगी जबरदस्ती घर से दो बकरियां उठा ले गए। जिनकी कीमत 15 हजार रुपये है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस अपने चौकीदार को बचाने में लगी है। महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चौकीदार का एक धमकी भरा आडियो भी वायरल किया है। जिसमें चौकीदार अपनी रौब दिखाता सुनाई पड़ रहा है। पुलिस ने मामला तूल पकड़ता देख नई स्क्रिप्ट तैयार की है। जिसमें दोनों पक्षों के विवाद को सुलह होना बताया है। पीड़िता का कहना है कि यह गलत है। हल्के में तैनात सिपाही व चौकीदार सुलह को धमका रहे हैं।

मोदी और योगी के अनुरूप विकसित हो रही है अयोध्या -रोली सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या रोली सिंह के 3 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब हुईं और अपने 3 वर्ष की विकास कार्यों को बताया उन्होंने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहां की अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है और इसका विकास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने देव तुल्य जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कया और कहा कि प्रथम दिन से उनके विकास के लिए कार्य कर रही हूं और जो भी समस्या मेरी समक्ष रखी जाती है या मुझे मालूम पड़ती है उसका तुरंत निस्तारण करती हूं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में अयोध्या जिला पंचायत को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है और अभी भी प्रयत्नशील हूं। उन्होंने बताया कि जनपद के प्राथमिकता के कार्यों में से ग्रामीण मार्गों के मरम्मत, गड्ढ़ा मुक्ति के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 35.750 किमी0 तथा कुल तीन वर्षों में 77.877 किमी० सड़कों का नवीनीकरण कार्य कराकर सुगम आवागमन हेतु जनता जनार्दन को समर्पित किया गया।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण मार्गों पर वर्ष 2023–24 में 2.620 किमी0 तथा कुल तीन वर्षों में 16.52 किमी० सड़कों का नवनिर्माण,ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2023–24 में 9.061 किमी० सी०सी० रोड तथा कुल तीन वर्षों में 19.881 किमी० सड़कों पर सी०सी० रोड का निर्माण किया गया। 2023–24 में 20.686 किमी० खड़ण्जा रोड तथा कुल तीन वर्षों में 45.546 किमी0 सड़कों पर खड़ण्जा रोड का निर्माण कार्य कराया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जल निकासी के लिए 2023–24 में 9.747 किमी० आर०सी०सी० नाला एवं कुल तीन वर्षों में 23.054 किमी० आर०सी०सी० नालों का निर्माण कराकर जनता जनार्दन को अर्पित की जा चुकी है और जल संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु 5807 एल०ई०डी० लाइटों को लगवाया जा चुका है तथा और लाइटें लगवाये जाने का कार्य प्रगति पर है और जिला पंचायत कार्यालय परिसर में जन सहयोग से मा० अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मा० उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या के कर कमलों द्वारा मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत अयोध्या की अध्यक्षता में किया गया तथा पार्कों का सौन्दर्याकरण कार्य भी कराया गया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार और जिला पंचायत के सभी सदस्य जनता के प्रति समर्पित होकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजीव सिंह महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, पूर्व पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, रुदौली के वर्तमान विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक सिंह उपस्थित रहे।

मेरा तो बेटा भी गया और इज्जत भी, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता का छलका दर्द, बहू ने छोड़ा परिवार

संवाददाता–देवरिया। कैप्टन अंशुमन के पिता की दर्द भरी दास्तां जानकर आप भी विचलित हो सकते हैं। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शाहिद के पिता ने जो कहा वह हर किसी को हिला कर रख देगा। कैप्टन अंशुमान सिंह ने आग में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। उनके इस बहादुरी भरे पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें कीर्ति चक्र से कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र प्रदान किया। यह शांतिकाल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति ने अपनी लव स्टोरी को सुनाई थी। वह उस समय काफी भावुक भी दिखी थीं। लेकिन अब शाहिद के पिता का बहू पर लगाए गए आरोप आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे। एक तरफ बेटा चला गया पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बहू भी परिवार का साथ छोड़कर चली गई। शहीद के पिता का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मेरी बहू मेरे परिवार का साथ छोड़कर क्यों चली गई। पिता ने बताया कि 18 तारीख को हमारी अंशुमान से एक दो मिनट की बात हुई। 19 तारीख को घटना हुई और हमारा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को शांति पूजा कराया उसमें भी वह नहीं आई। जब भी हम लोग फोन करते हैं। फोन परिवार के लोग उठाते हैं। सिर्फ एक ही जवाब मिलता है अभी बेटी को संभालने के लिए थोड़ा समय दीजिए। करीब 1 साल हो गए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब तक संभाल पाई कि नहीं कैप्टन के पिता ने आगे बताया कि मेरे घर से जाने के 10 दिन बाद वह एक स्कूल में पढ़ने लगी। जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होगी। वह किसी स्कूल में पढ़ा कैसे सकता है। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उन लोगों के इशारे पर हुआ है। कहा कि उनकी बहू यहां से जाने के बाद फोन तक नहीं उठाती है। उसने अचानक परिवार का साथ छोड़ दिया। बीते 26 जनवरी को जब उनके बेटे को सम्मान देने की बात हुई तो तभी उनकी बहू से बात हुई। इस दौरान हमने घर पर पूजा करने की भी बात बताई। लेकिन वह पूजा में भी नहीं आई। मेरी बहू स्मृति अपना सारा सामान पैक कर अपने साथ ले गई। आंखों में आंसुओं की धार लिए शहीद के पिता ने कहा कि मेरा बेटा मेरी बहू स्मृति से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने प्यार की परिभाषा और मर्यादा को भी तोड़ दिया। अब तो मेरा बेटा भी चला गया बहू भी चली गई। साथ में मेरी इज्जत भी चली गई। कैप्टन की मां ने चौनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरी बहू नोएडा वाले मकान में रहती थी। जब मेरी बेटी यहां से गई तो पता चला कि मेरी बहू अपना सारा सामान पैक करके चली गई। पिता ने कहा कि आर्मी की एक प्रक्रिया है उसके मुताबिक निकटतम परिजन को मुआवजा मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा उनकी बहू को मिला पेंशन उन्हें मिलेगी। इंश्योरेंस में दोनों को बराबर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार से 35 लाख उनकी बहू को मिला 15 लाख उन्हें मिले। मां ने कहा कि अब उनकी बहू कह रही है कि पैसा हमें सरकार से मिल रहा है।

(मरणोपरांत) सम्मानित किया। लेकिन आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर कैप्टन अंशुमान सिंह के माता–पिता ने एक चौनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बहू पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी चला गया। उनकी बहू अब उनका परिवार छोड़ कर चली गई। वह अपने साथ सब कुछ ले गई। राष्ट्रपति मुर्मु ने दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में दिवंगत अधिकारी की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को

मुख्य न्यायाधीश ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी

संवाददाता—अयोध्या। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने राम मंदिर की भव्यता को भी निहारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे पहले अपराह्न 3:15 बजे वे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के मध्य वे सरयू तट स्थित पर्यटन विभाग के होटल गए। जहां थोड़ी देर विश्राम के बाद वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां करीब 20 मिनट तक पूजा—अर्चना के बाद राममंदिर के लिए रवाना हुए। रामलला के दरबार में उन्होंने करीब 15 मिनट तक पूजा—अर्चना की। उन्होंने राममंदिर की भव्यता को भी निहारा। उन्हें मंदिर निर्माण के कार्यों के बारे में भी बताया गया। करीब ढ़ाई घंटे तक वे अयोध्या में रहे और शाम को 5:30 बजे चौधरी चरण सिंह घाट स्थित हैलीपैड से हेलीकाप्टर के जरिये वापस हो गए।

पांच लाख पशुओं को लगेगा एफएमडी का टीका

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। पशुपालन विभाग की तरफ से पांच लाख से अधिक पशुओं को एफएमडी का टीका लगेगा। बारिश के दौरान पशुओं में खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण होता है। इस बीमारी से बचाव के लिए विभागीय स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए विभागीय स्तर से आगामी 15 जुलाई से अभियान चलेगा। अभियान में साढ़े पांच लाख पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुल 23 टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही छह एम्बुलेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन्हें इमरजेंसी में प्रयोग किया जा सकेगा। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तीन सदस्यीय इस टीम में पशुधन प्रसार अधिकारी, पैरावेट व वैक्सीनेटर शामिल रहेंगे।

टापू बने गांव, राप्ती नदी ने पार किया खतरे का निशान

संवाददाता—गोरखपुर। नदियों के बढ़ रहे जलस्तर के बीच प्रशासन ने छह गांवों को बाढ़ प्रभावित मान लिया है। इनमें सदर तहसील के चार, सहजनवां और गोला का एक—एक गांव शामिल है। बड़हलगंज क्षेत्र के 20 से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं तो सहजनवां क्षेत्र में आमी के पानी में 50 एकड़ से ज्यादा फसल डूब गई है। कैंपियरगंज में भी समस्या बढ़ रही है। गुरुवार सुबह राप्ती नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। शाम चार बजे राप्ती खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। नदी में बढ़त जारी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरयू नदी का पानी अयोध्या पुल पर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद घटने लगा है। सहजनवां संवाददाता के अनुसार सहजनवां ब्लाक के दो गांवों के मैरुंड होने के साथ ही पिपरौली में भी आमी का कहर बरपा है। ब्लाक के आधा दर्जन गांवों में करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में सब्जी की खेती डूब गई है। बरहुआं के पास राप्ती का कटान जारी है।

एसडीएम दीपक कुमार गुप्ता ने मैरुंड गांव गहिरा का निरीक्षण कर लाइफ सपोर्ट जैकेट का वितरण किया। कैली के नेबूलाल ने बताया कि दो बीघा मक्का डूब गया है। आमी का पानी गांवों की तरफ बढ़ने लगा है। यही हाल रहा तो दो से तीन दिन में ब्लाक के कुछ और गांव मैरुंड हो सकते हैं। बोक्टा बरवार बांध पर बरहुआं गांव के सामने जारी कटान फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम न जाने पर लोगों में नाराजगी है। कैंपियरगंज क्षेत्र के बहबोलिया—रिगौली और खजुरगांवा —मिरिहिरिया के बीच के सिवान में लगभग पचास एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। मिरिहिरिया के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भवानी शंकर पांडेय, डोरा सिंह, प्रमोद पांडेय ने बताया कि मिरिहिरिया और बहबोलिया गांव के पास बंधे के पुलिया से पानी का रिसाव हो रहा है। रिगौली ग्राम प्रधान जोगिंदर निषाद, वीरेंद्र निषाद आदि ने बताया कि भरवलिया बंधे के पुलिया के रास्ते पानी आने से भरवलिया—भैसला सिवान की फसल डूबने का खतरा बना हुआ है।

राप्ती व आमी नदी का पानी कुसमौल—बांसगांव सड़क के दोनों तरफ फैल गया है। कुसमौल, भुसवल, जूड़ापुर, डेफरा, रेहरा, महादीह, हाटा, चंदौली, विश्रामपुर आदि गांवों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। बाढ़ के पानी से ताल नगरी, ताल ढेलहरा, अमियार, कुसमौल व बांसगांव में धान, मक्का व सब्जी की खेती डूब गई है। बड़हलगंज विकास खंड के कछारांचल में सरयू व राप्ती नदियों की बढ़त जारी है।

नागरिकों के लिए समस्या बन गई जल जीवन मिशन योजना

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। जिले की जहांगीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना नागरिकों के लिए समस्या बन गई है। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 जगदीशपुर और 15 नरियांव में कार्यदायी संस्था द्वारा बरती गई उदासीनता और मनमानी से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत जहांगीरगंज के वार्ड संख्या 14 जगदीशपुर में आरसीसी रोड के बगल नगर पंचायत से कराये जा रहे नाली निर्माण के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। सड़क खोदने के बाद उसकी मिट्टी को आरसीसी रोड पर ही रख दिया गया, जिससे बरसात के कारण लोगों को आवागमन में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशिक्षण में विभिन्न योजनाओं की दी जायेगी जानकारी

संवाददाता—संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नव उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर जागरूक करेगा। सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कार्यक्रम का आयोजन 16 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में होगा। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि नव उद्यमी प्रशिक्षण के साथ जागरूक करने के लिए 16 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद स्थित एसोसिएशन के कार्यालय प्रांगण में होना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के जरिए बेरोजगारों को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ नया उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैंकों के प्रतिनिधियों के द्वारा समुचित सहयोग प्रदान कराया जाएगा। कार्यक्रम में जनपद स्तरीय संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी उद्यमी को यदि उद्योग से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसका निदान कराया जाएगा।

31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराएं किसान

संवाददाता—गोरखपुर। खरीफ की फसल के बीमा के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जिंसवार प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं। केसीसी धारक किसानों (ऋणि किसान) के खाते से प्रीमियम की रकम काट दी जाएगी। जो किसान इसका लाभ लेने के इच्छुक नहीं है, उनको 7 दिन पूर्व सूचना बैंक को देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रबी व खरीफ सीजन में किसानों का प्रीमियम काटा जाता है। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में 31 जुलाई तक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बीमा कंपनी द्वारा फसल बार प्रीमियम की दरें निर्धारित कर दी गई है। जिन किसानों के केसीसी बने हैं उनके खाते से प्रीमियम की रकम काट ली जाएगी। केसीसी धारक ऐसे किसान जो बीमा कराने के इच्छुक नहीं है, उनका अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई के सात दिन पूर्व लिखित में सूचना बैंक में देनी होगी, अन्यथा उनका प्रीमियम काट दिया जाएगा। ऐसे किसान जो केसीसी कार्डधारक नहीं है वह जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं जिससे उनकी फसल बीमित हो जाएगी और नुकसान की स्थिति में ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उप कृषि निदेशक डॉ अरविंद सिंह ने किसानों से अपील किया है कि वह योजना का लाभ उठाने के लिए समय से अपना प्रीमियम कटवाएं जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में उनको क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके।

जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की बीमा कम्पनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिलेड नामित है। खरीफ 2024 में धान, मक्का, मूंगफली व अरहर फसल बीमा किया जा रहा है। किसान भाई कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ बटाईदार किसान भी उठा सकते हैं। उन्हें केवल एक प्रमाण पत्र देना होता है जिसमे उनके भूस्वामी द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि इस जमीन का सम्पूर्ण लाभ उन्हें न दे करके उनके बटाईदार को दिया जाय। फसल बीमा का लाभ लेने के लिए गैर ऋणी किसानों को बचत बैंक खाता का नवीनीकरण पासबुक, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, जमीन की खतौनी। जानकारी के लिए फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री 14447 अथवा प्रबंधक रंजीत सिंह के मोबाइल नम्बर 8353930425 और आलोक गुप्ता के मोबाइल नम्बर पर 7518207819 पर काल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।

लापरवाही के आरोप में नगर आयुक्त ने किया दो ड्राइवरों को बर्खास्त

संवाददाता—गोरखपुर। महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जोन 07 और 08 में साफ सफाई और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों की समीक्षा बैठक में बड़ी कार्रवाई हुई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड संख्या 27 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले आउटसोर्सिंग के 02 वाहन चालकों को बर्खास्त कर दिया। वहीं, वार्ड संख्या 74 से मेट एवं सुपरवाइजर को दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त सभागार में हुई बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र, जोन 07—08 के जोनल अधिकारी, समस्त सफाई निरीक्षक, समस्त सुपरवाइजर, सभी पार्षद एवं डोर टू डोर गाड़ियों के वाहन चालक मौजूद रहे। सभी वाहन चालकों को क्यूआर कोड के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज की नियमित वसूली करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कार्य में लापरवाही करने पर वार्ड संख्या 27 के 02 ड्राइवर अफजल और आकाश यादव को नगर निगम की सेवा से हटा दिया। वार्ड संख्या 74 में तैनात आउटसोर्सिंग के मेट एवं सुपरवाइजर को दूसरे वार्ड में तैनात करने के निर्देश दिए।

कम्पार्टमेंट प्रयोगात्मक परीक्षा 15 व 16 को

संवाददाता—संतकबीरनगर। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षाएं 20 जुलाई को होनी है। उससे पूर्व अर्द्ध छात्र, छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। जिसकी तिथि 15 व 16 जुलाई निर्धारित है। परीक्षा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में होगी। इसमें लिए परीक्षक नामित कर दिए गए हैं। रासायन विज्ञान के परीक्षक अभिषेक तिवारी, जीव विज्ञान के सुमित्रानन्दन पटेल, भूगोल के डॉ. राकेश सिंह और सैन्य विज्ञान के पुनीत कुमार त्रिपाठी को परीक्षक बनाया गया है।

चोरों के गैंग के एक आरोपी को 9 माह का सश्रम कारावास

संवाददाता—संतकबीरनगर। चोरों के गैंग के एक आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी सचिन पर सजा के साथ एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड की भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को चोरी की योजना बनाते समय गैंग के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामला जिले कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के ओसवाल डालडा फैक्ट्री के पास का है। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में उप निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप है कि 28 दिसम्बर 2023 को क्षेत्र भ्रमण पर थे। ओसवाल डालडा फैक्ट्री के पास तीन चोरों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक सचिन पुत्र रामचरन मोहल्ला बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है। आरोपियों के पास से नकब लगाने के दो सब्बल, एक पेचकश और दो चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सीजेएम अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते प्राइवेट स्कूल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) से आगे कुछ स्कूलों अपनी मनमानी चल रही है। आरटीई के नियमों के तहत लाटरी में नाम आने के बाद भी उनको प्रवेश के लिए पब्लिक स्कूल संचालक परेशान कर रहे हैं। आधार समेत अन्य जरूरी प्रपत्र लगे होने के बावजूद भी परेशान करने की नीयत से खामियां निकालकर प्रवेश के लिए टहला रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है। इसके तहत लाटरी निकलती है। इसके आधार पर संबंधित स्कूलों में अभिभावकों को प्रवेश कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस बीच अभिभावक जब स्कूल में प्रवेश कराने के लिए पहुंचते हैं उस समय स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रपत्र के नाम पर परेशान किया जाता है। जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल है उसी में आईटीई में प्रवेश का पात्र बच्चे के अभिभावक रहते हैं या नहीं इसके लिए सभासद या ग्राम प्रधान का पत्र मांगा जा रहा है। अभिभावक उनके घर चक्कर काट रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की मानें तो आरटीई में लाटरी तभी निकलती है जब प्रपत्र सही होते हैं। इसके अलावा भी पार्षदों से लिखवाने के नाम पर कुछ स्कूल परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कुछ शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं। आरटीई के तहत 25 फीसदी बच्चों का दाखिला लेना पब्लिक स्कूलों में अनिवार्य है।

कक्षा एक में आरटीई में गरीब परिवार, दिव्यांग, कैंसर पीड़ित माता या पिता के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश आरटीई लेने का नियम है। अभिभावक उसी वार्ड का रहने वाला हो, जिस वार्ड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। लाटरी से प्रवेश मिलने पर आठवीं तक निःशुल्क पढ़ाई बच्चे स्कूल में करते हैं। जिला समन्वयक अमित शुक्ल ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत जिले में चार चरणों में निकले लाटरी के तहत लक्ष्य 1569 के सापेक्ष 1302 बच्चों को पूरे जिले में अलग—अलग निजी स्कूलों में प्रवेश कराने की पहल की गई। प्रथम चरण में 114 के सापेक्ष 96, द्वितीय चरण में 675 के सापेक्ष 545, तृतीय चरण में 565 के सापेक्ष 460, चतुर्थ चरण में 215 के सापेक्ष 201 बच्चों का प्रवेश के लिए लाटरी निकली है।

देवेंद्र कुमार पांडेय, बीएसए ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत चार चरणों में जिलाधिकारी के निर्देशन में इस सत्र में 1302 बच्चों की लाटरी निकली है। सभी को संबंधित स्कूलों में प्रवेश के लिए कहा गया है। चयनित स्कूलों की ओर से प्रवेश न करने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नाले में गिरकर अधेड़ की मौत

संवाददाता—गोरखपुर। बड़हलगंज पटना चौराहे के पास हाईवे से सटे खुले नाले में गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर क्रियाकर्म के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया। पटना चौराहे के पास रहने वाले आसपास के दुकानदारों ने बताया कि सुबह चिल्लूपार मोहल्ले के हरिजन टोला निवासी दशरथ (50) नाले में गिरा पड़ा था। शुक्रवार की सुबह छह बजे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। बताया जाता है कि दशरथ गुरुवार से ही लापता था और घर नहीं आया था। उसकी एकमात्र विवाहिता पुत्री है। लोगों के आग्रह पर पुलिस ने उसकी पुत्री के लड़के को पंचनामा करवाकर शव को सौंप दिया।

ओपीडी पर्ची की नई व्यवस्था ने खड़ी की मरीजों के लिए दुश्वारियां

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिला अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी पर्ची कटवाने की नई व्यवस्था मरीजों के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है। नई व्यवस्था में जिन लोगों के पास बड़ी मोबाइल नहीं है उनकी पर्ची ही नहीं बन रही है। उन्हें बिना उपचार के वापस जाना पड़ रहा है। पर्ची काउंटर पर मरीजों से यही कहा जा रहा कि बड़ी मोबाइल लेकर आइए आनलाइन पर्ची ले जाइए। यह पर्ची नहीं मिलने से दर्जनों बीमार लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हुए या फिर वे निराश होकर घर चले गए।

शासन के निर्देश पर अब मरीजों को ओपीडी पर्ची ऑनलाइन मिल रही है। जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का डाटा फीड रहे। इस पर्ची से मरीज को पर्ची के लिए भाग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। चिकित्सक के पास सभी जानकारी ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही हो जाएगी। यदि संबंधित मरीज को हायर सेंटर रेफर भी किया जा रहा है तो वहां पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालने की जरूरत होगी। उसके बाद मरीज का डाटा आते ही उपचार चालू हो जाएगा। इस व्यवस्था के लिए आभा पोर्टल से भी पर्ची काटी जा रही है।

बदन दर्द से परेशान बघुआ गांव निवासी राम कुमार ने ओपीडी पर्ची के लिए काउंटर पर खड़े रहे। काउंटर पर बैठे कर्मी ने बताया कि बिना बड़ी मोबाइल के ऑनलाइन पर्ची नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो छोटी मोबाइल है। अब बड़ी मोबाइल कहां से ले लाऊं। इसके बाद वह मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर चले गए।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थी मोहम्मद सादिक सिद्दीकी पुत्र श्री करम हुसेन मकान नम्बर 266 नया बेगमखैर कालोनी नया पिकौरा दत्तूराय गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) का निवासी हूं। कुछ अभिलेखों में मेरा नाम सिद्दीकी मोहम्मद सादिक अंकित है इसे मोहम्मद सादिक सिद्दीकी समझा जाय।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से निर्गत मेरा उत्तर मध्यमा वर्ष 2012 अनुक्रमांक 770734 एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष अनुक्रमांक 850613 वर्ष 2013 का अंक पत्र वास्तव में खो गया है।

(रामानन्द पुत्र श्री रामशरन)
ग्राम— रामडीह तोरनी
पोस्ट— चढ़राव
थाना— सहजनवा
जिला—गोरखपुर

कोर्ट के आदेश पर चार लोगों पर एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज

संवाददाता—संतकबीरनगर। डीजे बजाने से मना करने पर एक परिवार की पिटाई करने वाले चार लोगों के खिलाफ बखिरा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बखिरा क्षेत्र के नावध निवासी उर्मिला पत्नी सुखराज का आरोप है कि होली के अवसर पर गांव के लोगों ने डीजे मंगवाया गया था। उसी बीच उसके भतीजे की मृत्यु हो गई। जिससे पूरा परिवार शोकाकुल था। उसके परिवार के लोगों ने डीजे बजाने से मना कर दिया। आरोप है कि विपक्षी उसके परिवार को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और मारापीटा। उसके मुंह में काले रंग की पोताई कर दिए। आरोप है कि लोग अमर्यादित व्यवहार भी किया। एसओ श्याम मोहन ने बताया कि लालजीत बेलहर निवासी इंद्रजीत यादव, हरिगोविंद, कुलदीप और नावध गांव निवासी विरेंद्र मौर्या के खिलाफ मारपीट, एससीएसटी एक्ट आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया।

GANGA ENTERPRISES

Village & Post-Parsauni Mithaura Bazar
District-Maharajganj UP Pin-273303

आवश्यकता है

सिक्योरिटी गार्ड/नाइट गार्ड के पद हेतु निर्धारित अर्हता निम्नानुसार हैं-

क्र0 सं0	विवरण	कार्मिकों की संख्या	प्रति माह मानदेय	माहवार व्यय सीमा	आयु सीमा	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1	सिक्योरिटी गार्ड/नाइट गार्ड	3	रू0 10500/—	रू0 31500/—	21 से 40 वर्ष	साक्षर होना आवश्यक है।	राज्य/जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का 02 साल अनुभव। अधिमानतः वह सेवानिवृत्त सैन्य/अर्ध—सैन्य कर्मी हो।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 13.07.2024 से 20.07.2024 तक आवेदन—पत्र स्वीकार किये जायेंगे एवं स्थानीय/जनपद के आवेदको को प्राथमिकता दी जायेगी। पद हेतु मे0 गंगा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट—परसौनी बाया मिठौरा, जनपद—महराजगंज पिन नं0—273207 को डाक / जमा करना होगा।

प्रो ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी
मे0—गंगा इण्टर प्राइजेज
मो0नं0—9621583583

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 456/2023
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती महोदय
जिला—बस्ती
काशीराम
बनाम
श्रीमती सुदामा देवी आदि
2. राम सहाय उम्र लगभग 76 साल पुत्र महादेव निवासी ग्राम व तप्पा पिलाई परगना नगर पूरब तहसील व जिला—बस्ती
—प्रतिवादी द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 06—08—2024

हरगाह के आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

ऊफनाई राप्ती, रेगुलेटर से पानी के रिसाव से मचा हड़कंप

संवाददाता—संतकबीरनगर। राप्ती नदी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं सरयू नदी स्थिर है, लेकिन नदी और तटबंध के बीच बसे 32 गांव के लोग सहमे हैं। इसी बीच रामपुर—मखदुमपुर तटबंध पर बने रेगुलेटर से पानी का रिसाव होने लगा, जिसकी सूचना पर हड़कंप मच गया। बाढ़ खंड के अधिकारी पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद उसे ठीक कराए। नदियों के जलस्तर को देखते हुए अधिकारी तटबंध पर डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य, पशुपालन, पंचायती राज समेत अन्य विभागों को सतर्क कर दिया गया है। करमैनी—बेलौली तटबंध पर राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चौथे दिन राप्ती का जलस्तर 79.18 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे में राप्ती लाल निशान से महज 32 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी बांध पर जलस्तर का ना तो कोई दबाव है न ही तटबंध को कोई खतरा है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। सहायक अभियंता राम उजागर लाल के नेतृत्व में चार अवर अभियंता समेत अन्य कर्मचारी तटबंध और जलस्तर की निगरानी में लगे हैं। कटान व रेनकट मुक्त तटबंध को रखने के लिए ड्रेनेज खंड द्वितीय द्वारा तटबंध पर जगह—जगह मिट्टी इकट्ठा किए गए हैं। बेलौली और नौगो में तटबंध से जलस्तर सट रहा है लेकिन जलस्तर का दबाव बांध पर नहीं है। अधिकारियों की टीम 19.2 किलोमीटर तटबंध की जहां निगरानी कर रही है। सहायक अभियंता का कहना है कि तटबंध पर सभी रेनकट भरे जा चुके हैं। जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन नदी के पानी का दबाव करमैनी—बेलौली तटबंध पर कहीं से नहीं है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। जलस्तर तथा तटबंध की लगातार निगरानी कराई जा रही है। आवश्यकता अनुसार बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं।

वही धनघटा में सरयू नदी का जलस्तर भले ही स्थिर हो रहा। लेकिन बाढ़ का पानी नदी और एमबीडी बांध के बीच फैलते हुए कई गांव को घेरने में लगा है। वहीं रामपुर मखदुमपुर बांध पर रामपुर के पास लगे रेगुलेटर सुबह रिसाव होने लगा। जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने तीन घंटे मशक्कत के बाद उसे सही किया।

नदी का जलस्तर सुबह खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। शाम को नदी का पानी स्थिर तो जरूर हुआ लेकिन दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जिससे बाढ़ के पानी से गायघाट दक्षिणी, दौलतपुर, खालेपुरवा, ढोलबजा, गुनवतिया, चकदहा, सियर कला, नारायनपुर आदि गांव बाढ़ के पानी से घिरने लगे हैं। गायघाट दक्षिणी के प्रधान बालेंद्र उर्फ पप्पू ने बताया कि बाढ़ से जहां फसलें जलमग्न हो गई हैं। वही गांव के करीब पानी पहुंचने से गांव के रास्ते अवरुद्ध होने लगे हैं। प्रधान का कहना है कि अभी लोगों पर नाव की जरूरत नहीं है। लेकिन पानी इसी तरह बढ़ा तो दो दिन के अंदर नाव की आवश्यकता पड़ जाएगी।

दैनिक
भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल bhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com